सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. रमेश बैस

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२७ फरवरी २०२३

सन्मानीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यगण,

वर्ष २०२३ में, राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

२. मेरी सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे और अन्य महान स्वप्नद्रष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकथित किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है।

३. जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

मेरी सरकार ने, "जय जय महाराष्ट्र माझा" को राज्य गान के रूप में १९ फरवरी, २०२३ से स्वीकार किया है, जिससे राज्य गान की हमारी अपेक्षा पूरी हो गई है।

४. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित उच्चतम न्यायालय में दाखिल मूल वाद में, महाराष्ट्र का वाद-प्रतिवेदन मजबूती से प्रस्तुत किया है और उसे हम निरंतर चलाते रहेंगे।

मेरी सरकार ने, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले मराठी भाषिक लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है और उसका कार्यान्वयन भी शुरू किया है।

५. कार्यभार संभालने के पश्चात्, मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता यह रही है कि राज्य में कोविड़ के बाद की अर्थव्यवस्था को पुनःजिवित करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।

भारत की आज़ादी के ७५ वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने पहले चरण के रूप में, ७५,००० सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है।

६. कार्यभार संभालने के पश्चात्, सरकार ने, न्यायालय के न्यायनिर्णय से जो मराठा उम्मीदवार प्रभावित हुए थे, उनके लिये १ हजार ५५३ अधिसंख्य पद सृजित करने के लिए एक विशेष विधि की अधिनियमिति द्वारा मराठा आरक्षण के अधीन नियुक्तियों को संरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया है।

७. राज्य, वर्ष २०२२-२३ में पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को एक विशेष सहायता के रूप में ८ हजार करोड़ रुपयों से अधिक के आबंटन के लिए सन्माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति राज्य कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। मुझे आपके साथ यह वास्तविकता बताते हुए खुशी हो रही है कि, अब तक ५ हजार ८८४ करोड़ रुपये पहले से ही मंजूर किए गए हैं और वह परियोजनाएँ अच्छी तरह से शुरू हुआी है।

८. मेरी सरकार, वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ में ६०० रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। १ लाख २५ हजार नौकरियां सृजित करने के लिए ४५ कंपनियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है। ८७ हजार ७७४ करोड़ रुपयों के निवेश की राशि के चौबीस परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए गये हैं जिसमें से ६१,००० नौकरियाँ सृजित होनेवाली है।

९. मेरी सरकार ने, जनवरी २०२३ में, दावोस वैश्विक निवेशन सम्मेलन में १ लाख ३७ हजार करोड़ रुपयों के निवेशन के लिए १९ कंपनियों के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए है।

१०. मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के अधीन ४ लाख ८५ हजार ४३४ युवाओं तथा २ लाख ८१ हजार ५४१ कृषकों के प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

११. मेरी सरकार ने, युवाओं को कुशल बनाने तथा रोजगार सृजित करने के लिए गोंदिया और गढ़चिरोली जिले में दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किये हैं। १००० से अधिक आईटीआई अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक संकाय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

१२. मेरी सरकार ने, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पति-पत्नी की पेंशन १०,००० रुपयों से बढ़ाकर २०,००० रुपये प्रति महीना इतनी दोगुना कर दी है। इससे, राज्य के ५ हजार ४०६ स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ होगा।

१३. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के शहीदों के विधिक वारिसों की पेंशन भी १०,००० रुपयों से बढ़ाकर २०,००० रुपये प्रति महीना दोगुना कर दी है।

१४. मेरी सरकार ने, "आपातकाल अवधि के दौरान, जो लड़े थे, उन व्यक्तियों के सम्मान की योजना" को पुनःप्रारम्भ किया है। इस योजना में कुल ४ हजार ४३८ लाभार्थीयों को शामिल किया गया है।

१५. महाराष्ट्र, देश का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में १४.२ प्रतिशत का योगदान देता है और भारत की कुल निर्यात के १७.३ प्रतिशत की निर्यात के साथ निर्यात में भी अग्रणी रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। मेरी सरकार, वर्ष २०२६-२७ तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सन्मानीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिये, राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

१६. मेरी सरकार ने, १३ से १६ दिसम्बर, २०२२ के दौरान मुंबई में जी-२० शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का और पूने में १६ और १७ जनवरी, २०२३ के दौरान, जी-२० शिखर सम्मेलन के मूलभूत सुविधा कार्य दल की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इसमें सहभागी प्रतिनिधियों ने, शिखर सम्मेलन की बहुत सराहना की है।

१७. मेरी सरकार ने, उद्योगों के लिए कारोबार में सुकरता लाने के लिए "मैत्री" नामक एक एकल खिडकी पोर्टल के ज़रिए उद्योगों के लिए आवश्यक ११९ ऑनलाईन सेवाएँ उपलब्ध की है।

१८. वस्त्रोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मेरी सरकार, नई कपास प्रक्रिया ईकाइयों की स्थापना करने और वस्त्रोद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करने के लिए " एकीकृत और स्थायी वस्त्रोद्योग नीति २०२३-२८ " बना रही है। जिससे, राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

१९. मेरी सरकार ने, वड़ाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक मुंबई मेट्रो लाईन-११ परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई १३ किलोमीटर है, जिसमें दो उन्नत और आठ भूमिगत स्थानकों का समावेश है।

२०. " गति शक्ति ", पर जोर देते हुए, मेरी सरकार ने, तीन शहरों में, मुंबई में ३० किलोमीटर, नागपुर में ४० किलोमीटर तथा पूना में ३२ किलोमीटर लंबाई के मेट्रो मार्ग शुरू किये है।

२१. मेरी सरकार ने, "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) २.०" की तर्ज पर "स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन (शहरी) २.०" शुरू किया है।

२२. मेरी सरकार ने, मुंबई में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए "हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे-आपला दवाखाना" के अधीन, ७२ अस्पताल शुरू किये गये हैं और मार्च, २०२३ तक मुंबई में १८ नए बहुचिकित्सालय और नैदानिक केंद्रों तथा १२३ "आपला दवाखाना" शुरू करना प्रस्तावित किया है।

२३. मेरी सरकार ने, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के ज़रिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज़ पर " महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान-मित्र " की स्थापना की है। मित्र, राज्य के विकास के लिए नीतिगत, तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करनेवाला प्रबुद्ध मंडल होगा।

मेरी सरकार ने, आर्थिक और अन्य आनुषंगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिये "आर्थिक सलाहकार परिषद" की भी स्थापना ही है।

२४. आदरणीय प्रधानमंत्री ने, ११ दिसम्बर, २०२२ को नागपुर से शिर्डी के बीच का ५२१ किलो मीटर का " मुंबई नागपुर हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुतगति महामार्ग " का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन से ३१ जनवरी, २०२३ तक इस महामार्ग पर कुल ७ लाख ८४ हजार ७३९ वाहनों ने यात्रा की है।

२५. मेरी सरकार, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना, एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हायब्रिड ॲन्यूटी योजना के ज़रिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है।

" प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना " के अधीन, अब तक २६ हजार ७३१ किलोमीटर लंबाई का सड़क संनिर्माण कार्य पूरा किया गया है।

२६. मेरी सरकार ने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के ज़रिए लगभग ५,००० गाँव में "जलयुक्त शिवार अभियान २.०" कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया है। जल भण्डार क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए "गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार" की योजना निरंतर जारी रखी जायेगी।

२७. मेरी सरकार ने, केंद्र द्वारा प्रायोजित "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अधीन २७ परियोजनाओं तथा "बलिराजा जलसंजीवनी योजना" के अधीन ९१ परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी की गई परियोजनाओं से "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अधीन ३ लाख २७ हजार हेक्टर्स सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है तथा "बलिराजा जलसंजीवनी योजना" के अधीन १ लाख ७३ हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है। अब तक, २ लाख ९५ हजार १२७ हेक्टर्स के कमान क्षेत्र पर पाईप वितरण नेटवर्क पूरा किया गया है।

२८. मेरी सरकार ने, ३३ हजार ४०० करोड़ रुपयों की प्राक्कलित लागत होनेवाली २९ सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। यह २९ परियोजनाएँ पूरी होने के पश्चात्, ५ लाख ८६ हजार ४३९ हेक्टर्स भूमि सिंचित होगी।

२९. किसानों को दिन के समय में बिजली प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने, "मिशन-२०२५" कार्यक्रम शुरू किया है जिसके द्वारा ३० प्रतिशत कृषि फीड़रों को अगले तीन साल में सौरउर्जित किया जायेगा।

३०. पाँच लाख से अधिक आवासों के संनिर्माण को पूरा करने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" और राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृहनिर्माण योजना के कार्यान्वयन के लिए "अमृत महा आवास अभियान" शुरू किया गया है।

३१. आदरणीय प्रधानमंत्री के ' हर एक के सिर पर छत ' के सपने को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में "प्रधानमंत्री आवास योजना" के कार्यान्वयन को गति देने के लिए सरकार वचनबद्ध है।

३२. मेरी सरकार, पुलिस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लिए दीर्घवधि, मध्यम अवधि और तत्काल उपाय कर रही है और म्हाडा की मदद से, मुंबई में पुलिस आवासों का पुनर्विकास करने का विनिश्चय किया है।

३३. मेरी सरकार ने, पुलिस कर्मचारी और उनके वारिसों को, जो दिनांक १ जनवरी २०११ तक बी.डी.डी. चाल में रह चुके है उन्हे १५ लाख रुपयों की संनिर्माण लागत पर स्वामित्व आधार पर ५०० स्क्वेअर फीट के पुनर्विकसित निवासस्थान का आबंटन करने का निर्णय लिया है।

३४. मेरी सरकार ने, राज्य में, "जल जीवन मिशन" के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में १ करोड़ ५ लाख ७३ हजार घरेलू कनेक्शन प्रदान किये है। स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए १ हजार ४४२ गाँव में "अटल भूजल योजना" कार्यान्वित की जा रही है।

३५. मेरी सरकार ने, वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वन या वन्यजीवन की सुरक्षा करते समय जंगली जानवरों के हमले में उनकी मृत्यू होने के मामले में उनके वारिसों को २५ लाख रुपये तथा स्थायी विकलांगता के मामले में ३ लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने का विनिश्चय किया है। जंगली जानवरों के हमले के मामले में मानवहानि होने के कारण अदा की जानेवाली वित्तीय सहायता की रक़म १५ लाख रुपयों से बढ़ाकर २० लाख रुपये की गई है।

३६. रामसर कन्व्हेशन ने, उक्त क्षेत्र में के आर्द्र भूमि और वन्यजीवों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए, ठाणे खाड़ी फ्लेमिंगो अभयारण्य को "रामसर स्थल" के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार ने, वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ के अधीन, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों और पौधों तथा वहाँ के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए, राज्य में, ११ नए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किये हैं।

३७. मेरी सरकार ने, राज्य में हल्दी की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए हिंगोली जिले में "बालासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हल्दी) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र" स्थापित किया है। इस केंद्र के लिये, १०० करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध किया जायेगा।

३८. संयुक्त राष्ट्र ने, २०२३ को मिलेट "आंतर्राष्ट्रिय मिलेट वर्ष" के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार ने, किसानों के बीच में मिलेट को लोकप्रिय बनाने और मिलेट का क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए २०० करोड़ रुपयों के प्रावधान के साथ "महाराष्ट्र मिलेट मिशन" शुरू किया है। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान, हैद्राबाद के सहयोग से सोलापुर में "मिलेट उत्कर्षता केंद्र" स्थापित किया जायेगा।

३९. मेरी सरकार ने, संपूर्ण कोंकण विभाग में साथ ही साथ, कोल्हापुर जिले के चंदगड और आजरा तहसिल में काजू फल फसल विकास योजना को मंजूरी दी है और उसी प्रयोजन के लिए, ५ वर्ष के लिए १ हजार ३२५ करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

४०. मेरी सरकार ने, "महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना" के अधीन अल्पकालिक फसल ऋण की नियमित रूप से पुनर्अदायगी करनेवाले किसानों को ५०,००० रुपयों का प्रोत्साहन लाभ दिया है। इस योजना के अधीन, १२ लाख ८४ हजार लाभधारियों के खाते में, ४ हजार ६८३ करोड़ रुपयों की रक़म सीधे ऑनलाईन जमा की गई है।

मेरी सरकार ने, ३४ हजार ७८८ किसानों ने, २९ भूविकास बँक की ओर से लिए गए ९६४ करोड़ रुपयों के बकाया ऋण को माफ़ करने का भी निर्णय लिया है।

४१. मेरी सरकार ने, किसानों के घर-द्वार पर जाकर पशुओं का शत प्रतिशत नि:शुल्क निवारक टिकाकरण किया है। जिन्होने लम्पि त्वचा रोग के कारण उनके पशुओं को खो दिया है ऐसे किसानों और पशुधन स्वामियों की सहायता की है। इस महामारी से लड़ने के लिए औषधि, टीका और उपकरणों के लिए प्रति जिले को ३ करोड़ रुपयों का निधि दिया गया है।

४२. मेरी सरकार ने, पशुपालन विभाग की पशुचिकित्सा जैविक उत्पादन संस्थान, पुणे में लम्पि त्वचा रोग निवारक टिका का उत्पादन शुरू करने का विनिश्चय किया है।

४३. भारत सरकार ने, "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के अधीन नौ मछली लॅन्डिंग केंद्रों को प्रशासकीय अनुमोदन दिया है और मत्स्योद्योग और जलीय कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि के अधीन, समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पाँच मछुवाही बन्दरगाह को भी मंजूरी दी है।

४४. मेरी सरकार, लोगों की सुविधा के लिए सर्वेक्षण और शहर सर्वेक्षण नक्शा इस अधिकारों के अभिलेखों अर्थात् ग्राम प्रपत्र क्रमांक ७/१२ उद्धरण और सम्पत्ति कार्ड़ से जुड़नेवाली जीआईएस आधारित पोर्टल शुरू करेगी।

४५. किसानों के बीच कृषि भूमि के कब्जे और हक्र से संबंधित विवादों का निपटान करने और समाज में सौहार्द निर्माण करने के लिए मेरी सरकार ने, भूमि दस्तावेज के विनिमय विलेख घटाकर नाममात्र स्टाम्प शुल्क १,००० रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस १,००० रुपये करने के लिये "सलोखा योजना" के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

४६. मेरी सरकार ने, सामान्य नागरिकों को किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए, राज्य में, केंद्र सरकार के "आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन" को कार्यान्वित किया है। इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम के अधीन, १८ हजार ९७६ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और १३ हजार, ४७३ स्वास्थ्य सुविधाओं को रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा राज्य में, १९ लाख ४८ हजार ५१७ नागरिकों को आयुष्यमान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड़ जारी किए गए है।

४७. मेरी सरकार ने, २६ सितम्बर, २०२२ से १८ वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और माताओं की व्यापक स्वास्थ्य जाँच के लिए विशेष अभियान "माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित" को प्रारम्भ किया है। इस अभियान के अधीन, महिलाओं के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाये जा रहे हैं।

४८. मेरी सरकार ने, उस्मानाबाद में, एक संलग्न अस्पताल के साथ १०० छात्रों की क्षमतावाला एक नया सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया है।

४९. मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" के ७ वें चरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस योजना के अधीन "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" के ७ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति महीना प्रति व्यक्ति अतिरिक्त ५ किलो ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) दिए गए है।

तृतियपंथी व्यक्तियों को अन्न सुरक्षा का लाभ देने के लिए रेशन कार्ड़ दिए जायेंगे।

५०. "बालसंगोपन योजना" के अधीन, मेरी सरकार ने, अभिभावकों को प्रति बच्चे, प्रति महीना प्रोत्साहन भत्ता १,१०० रुपयों से बढ़ाकर २,२५० रुपये किया है तथा बच्चों के पालनपोषण के लिए एनजीओं को १२५ रुपयों से बढ़ाकर २५० रुपये किया है।

५१. राज्य में संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल जानकारी और सहायता देने के लिए, मेरी सरकार ने, अलग से टोल फ्री नंबर "१८१ महिला हेल्पलाईन" को शुरू करने का निर्णय लिया है।

५२. मेरी सरकार ने, ३६ जिलो में किराए के आधार पर ७२ सरकारी छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति और विशेष पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों से संबंधित मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा पानेवाले छात्रों के लिए प्रत्येक छात्रावास में १०० छात्रों की क्षमता के साथ प्रति जिले में एक छात्रावास लडकों के लिए और एक छात्रावास लड़कियों के लिए होगा।

५३. मेरी सरकार ने, वर्ष २०२२-२३ के दौरान मराठा समुदाय के ५०० छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाओं की तैयारी के लिए, " छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान, प्रशिक्षण और मानव विकास संस्था (सारथी) " द्वारा निधि का वितरण किया है और " छत्रपति राजाराम महाराज छात्रवृत्ति " के लिए ९वीं से १२वीं तक की कक्षा में से २५,००० छात्रों का चयन किया है।

५४. मेरी सरकार ने, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास निगम द्वारा, मराठा समुदाय के १३ हजार ६८९ लाभधारियों को १५३ करोड़ रुपये ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित किए गए हैं।

५५. मेरी सरकार ने, मराठा समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएँ मंजूर की है। " डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना " के अधीन १ लाख ७४ हजार ८५ छात्र लाभान्वित हुए हैं। " राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क भत्ता योजना " के अधीन १२ लाख ५४ हजार १४५ छात्र लाभान्वित हुए हैं। "डॉ. पंजाबराव देशमुख छात्रावास योजना" के अधीन १० जिलों में छात्रावास शुरू करने का प्रस्तावित किया है।

मेरी सरकार, उच्चतम न्यायालय में सभी प्रयास करके मराठा आरक्षण पुनःप्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है।

५६. मेरी सरकार ने, वी जे एन टी प्रवर्ग के आश्रम विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से और अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में "निपुण भारत योजना" शुरू की है।

५७. दिव्यांगों के विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र " दिव्यांग विभाग " का निर्माण किया गया है।

५८. राज्य में, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जन जीवन, मवेशियों, कृषि फसलों, घरों और सार्वजनिक सम्पत्तियों को हुए नुकसान के लिए मेरी सरकार ने, उन व्यक्तियों को राज्य आपदा उत्तरकारी निधि के मानदंडों के दोगुनी दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार ने, प्रभावित व्यक्तियों को ७ हजार ३१२ करोड़ रुपयों का निधि दिया है।

५९. मेरी सरकार ने, अनुसूचित जनजातियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्य में "शबरी आदिवासी घरकुल योजना" का कार्यान्वयन किया है। वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए योजना के अधीन २४ हजार ७५ आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा उसके लिए आवश्यक संपूर्ण निधि दिया जायेगा।

६०. मेरी सरकार ने, १२१ आश्रम विद्यालयों को आदर्श आश्रम विद्यालयों के रूप में घोषित किया है और इन विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएँ, आभासी कक्षाएँ, टॅब लॅब, कम्प्यूटर लॅब शुरू किए जायेंगे।

६१. मेरी सरकार ने, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, "न्यायपालिका के लिए संरचना सुविधाओं का विकास" योजना के अधीन वर्ष २०२२-२३ में, १८ न्यायालय भवनों के संनिर्माण कार्य के लिए लगभग ७७२ करोड़ रुपये तथा न्यायाधिशों के लिए २३ आवासीय क्वार्टरों के लिए लगभग ११० करोड़ रुपयों तक का प्रशासकीय अनुमोदन मंजूर किया है।

मेरी सरकार ने, ठाणे जिले के बेलापूर, नवी मुंबई में एक नये परिवार न्यायालय को स्थापित करने के लिये प्रशासकीय अनुमोदन को मंजूरी दी है।

६२. मेरी सरकार ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक जीवन से नई पीढ़ी को परिचित करने के लिए विरासती किलों के संवर्धन और संरक्षण को प्राथमिकता दी है।

६३. भारतीय स्वातंत्रता के ७५ वर्ष के अवसर पर मेरी सरकार, "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के अधीन १५ अगस्त, २०२३ तक कई विशेष घटनाओं, गतिविधियों, योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उक्त प्रयोजन के लिए तैयार की गई वेबसाईट पर १ लाख ७५ हजार से अधिक कार्यक्रम और गतिविधियों का रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

६४. मेरी सरकार, मराठवाड़ा मुक्ति दिन के ७५ वर्ष पूरे होने के अवसर पर १७ सितम्बर, २०२२ से १७ सितम्बर, २०२३ तक " मराठवाड़ा मुक्ति दिन अमृत महोत्सवी वर्ष " के रूप में मना रही है। मेरी सरकार, मराठवाड़ा विभाग के आठ जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

६५. मेरी सरकार ने, " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना " के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण के ज़रिए "सुविधा सम्पन्न कुटुंब मिशन और सर्वांगिण ग्रामसमृद्धि योजना" के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

६६. मेरी सरकार ने, " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना " के अधीन सिंचाई कुओं के लिए लागत सीमा को ३ लाख रुपयों से बढ़ाकर ४ लाख रुपये तक कर दी गई है। सरकार, " महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना " के अधीन "अमृत महोत्सवी फल वृक्ष, वृक्षारोपण और पुष्प वृक्षरोपण कार्यक्रम" के पुनर्गठन में छोटे किसानों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन केले, ड्रॅगन फ्रुट, एवोकाडो, अंगूर, सोनचाफा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और जायफल जैसी अतिरिक्त फसलों को नये सिरे से शामिल किया गया है।

६७. मेरी सरकार ने, सरकारी मान्यताप्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को ग्राह्य आर्थिक सहायता में वर्ष २०२२-२३ से ६० प्रतिशत तक वृद्धि की है।

६८. राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अनुसार, इंजीनियरिंग उपाधि और डिप्लोमा के छात्रों को मराठी और अंग्रेजी इन दोनों माध्यम से अभ्यासक्रम की पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए, शिक्षा सामग्री मराठी में उपलब्ध की गई है।

६९. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतर्राष्ट्रिय संगीत महाविद्यालय की ओर से विभिन्न संगीत पाठ्यक्रम शुरू किए गए है।

७०. महाराष्ट्र उच्चतर शिक्षा ॲटलास वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध की जायेगी।

७१. मेरी सरकार, केंद्र प्रायोजित " पीएम श्री विद्यालय योजना " का ८४६ विद्यालयों में कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अधीन, ५ वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक विद्यालय को १ करोड़ ८८ लाख रुपये दिए जायेंगे।

७२. मेरी सरकार, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पात्रता मानदण्ड के अनुसार सहायता अनुदान देगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए १ हजार १६० करोड़ रुपयों का निधि मंजूर किया गया है। इस निर्णय का लाभ ६०,००० से अधिक अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद को मिलेगा।

७३. मेरी सरकार ने, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण सेवकों का मानदेय दोगुना से अधिक करने का निर्णय लिया है।

७४. मैं, मध्यप्रदेश में हुए ५वीं खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र के खिलाडियों का अभिनंदन करता हूँ।

७५. मेरी सरकार का, वाई, जिला सातारा में महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडल के लिए एक नया कार्यालय बनाने और इस स्थान पर तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी का स्मारक स्थापित करने का इरादा है।

७६. मेरी सरकार ने, मराठी भाषा भवन, चर्नी रोड, मुंबई में मराठी भाषा विभाग के अधीन आनेवाली चार क्षेत्रीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने का निर्णय लिया है।

७७. वैश्विक स्तर पर मराठी भाषा का प्रचार-प्रसार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने, मुंबई में पहली बार ४ जनवरी से ६ जनवरी, २०२३ तक "मराठी तितुका मेळवावा"- " विश्व मराठी सम्मेलन " का आयोजन किया था। प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का मेरी सरकार का इरादा है।

सन्मानीय सदस्यों, इस सत्र में, नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों, विनियोग विधेयकों और अन्य विधिविधान आपके विचारार्थ रखे जायेंगे। मुझे यह विश्वास है कि, सन्मानीय सदस्य सम्मिलित होंगे और महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जानेवाले इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे।

मैं फिर से एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!